ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

गायब हो गया हमारी थाली से सेंधा नमक

रविवारीय, 03 - 09 नवंबर 2019, वर्ष- एक, अंक-13, रांची | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN 00962 | कुल पृष्ठ 4 | मूल्य 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

मेकॉन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 मना

राँची :मेकॉन में 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। *ईमानदारी- एक जीवन शैली* के संकल्प के साथ मेकॉन, राँची में 28.10.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे शपथ समारोह के साथ इसका शुभारंभ हुआ । मुख्यालय के कर्मियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतुल भट्ट ने सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई । मुख्य सतर्कता अधिकारी उपकार कुमार केडिया ने इस अवसर पर सभी वरीय अधिकारियों एवं कर्मियों को संबोधित किया। शपथ समारोह में भारी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ सलिल कुमार, निदेशक (परियोजना) व श्री आर. एच. जुनेजा, निदेशक (वित्त) की भी उपस्थिति सराहनीय रही ।

सीएमपीडीआई के 8 सदस्यों को भावभीनी विदाई दी गई

रांची : सीएमपीडीआई परिवार के 8 सदस्यों को ''कांफ्रेंस हॉल'' में सेवानिवृत्ति के मौके पर आयोजित एक समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। इनमें आर0डी0 बहादुर-मुख्य प्रबंधक (उत्खनन), एस0के0 त्रिवेदी- मुख्य प्रबंधक (लाइब्रेरी), पी0के0 सिन्हा-मुख्य प्रबंधक (ईएंडएम), डॉ0 एस0एस0राव-मुख्य प्रबंधक (सिस्टम), धनेश्वर महतो-कार्यालय अधीक्षक, राजीव रंजन-वरीय वैज्ञानिक सहायक, श्रीमती नुरूस सबा-कैट-3 एवं जय शंकर महतो-वरीय एसी/यूपीएस स्टेंडेंट शामिल हैं। इस मौके पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री एस0 सरन, निदेशक (तकनीकी/ईएस) श्री के0के0 मिश्रा एवं निदेशक (तकनीकी/पीएंडडी) श्री ए0के0 राणाने सेवानिवृत्त कर्मियों को पुष्पगुच्छ, मान-पत्र, प्रतीक चिह्न व शॉल देकर कम्पनी की ओर सम्मानित किया।

राजधानी के ज्यादतर तालाब हैं प्रदूषित, कंक्रीट से बेतरतीब सौंदर्यीकरण के कारण इनके अस्तित्व पर संकट

बर्बाद हो रहें हैं रांची के सारे जलाशय

लाइन तालाबः प्रदूषण से मछलियों के मरने के बाद छठ पर्व में साफ सफाई कर गंगाजल डाला गया

चुटिया ट्रांसफर्मर तालाबः पानी में आग लग जाती है

वरीय संवाददाता

रांची :हाल ही में हुये एक सर्वे के मुताबिक रांची और झारखंड की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि आदमी की जिंदगी चार से पांच साल घट गयी है। प्रदूषित हवा के साथ साथ रांची के सारे तालाब और बड़े जलाशय भी भयंकर प्रदूषण का शिकार हो चुके हैं। भले इनके साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का खेल सालों से चल रहा है लेकिन हकीकत में एक एक कर सारे तालाब बर्बाद हो रहे हैं।

हाल ही में लाइन तालाब में हजारो मछलियां मर गयीं। चारो ओर दुर्गंध फैल गयी। इसके बाद यहां सफाई कर दी गयी, छठ के लिये घाट सजा दिये गये और पटना से गंगाजल मंगा कर इसमें डाल दिया गया। नगर निगम से लेकर सरकार की ये सारी करतूत एक मजाक से ज्यादा कुछ नही है। लाइन तालाब में प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन की कमी से 2017 में भी हजारो मछलियां मरी थीं। तब मछली पालने वाले कुछ लोग मरी हुई मछली लेकर नगर निगम प्रशासक के चैंबर में घुस गये थे और प्रशासक ने उन्हें डांट कर भगा दिया था। दुर्गा पूजा के बाद तालाब में मुर्तियां विसर्जित की गयीं थीं, लेकिन उसके बाद इस तालाब की सफाई नहीं की गयी, इस कारण से ही तालाब में प्रदूषण स्तर बढते चला गया और हजारों मछलियां ऑक्सीजन की कमी से मर गयीं। 2012 से ही इस तालाब को वाटर पार्क बनाने और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इस काम में इसके किनारों को कंक्रीट से बांध दिया गया इसी कारण से इसमें जल का प्राकृतिक प्रवाह नहीं रहा और ऑक्सीजन की कमी होती गयी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइन तालाब के साथ ही ये हश्र हुआ हो। रांची के तकरीबन सारे तालाबों को सौंदर्यीकरण के नाम पर एक तरह से बर्बाद किया जा चुका है। डिस्टिलरी तालाब लुप्त हो चुका है, बरियातू का जोड़ा तालाब कंक्रीट निर्माण के कारण कुछ समय पहले जलरहित हो गया था,चुटिया का तालाब अब बरसात में भी जलरहित रहता है, और गर्मियों में बच्चे इस तालाब में क्रिकेट खेलते हैं, मधुकम तालाब बर्बाद हो चुका है। करमटोली तालाब पर पर्यावरणविदों की माने तो आज फव्वारों से सजे इस तालाब का भी देर सबेर हश्र बुरा ही होना है। बड़ा तालाब हो या गोंदा जलाशय सभी प्रदूषित, सड़ रहे जलकुंभी से हरे बदबूदार पानी से भरे हुये हैं। सफाई या सौंदर्यीकरण के नाम पर इन तालाबों पर करोड़ो रूपये फूंके जा चुके हैं, पर नतीजा कुछ नहीं है। कुछ दिनों पहले कांके डैम में गंगा आरती की गयी थी, लेकिन हकीकत मे कांके डैम का जल किसी आरती पूजन के लायक है ही नहीं। पिछले साल ही यहां भी हजारों मछलियां प्रदूषति जल और ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गयीं थी। ●

तिलैपिया मछली भी नहीं बची

लाइन तालाब में हम प्रदूषण स्तर इतना बढा हुआ है कि तिलैपिया मछली भी नहीं बची। तालाब में मरी मछलियों में तिलैपिया मछली की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। तिलैपिया प्रदूषित जल में भी रह लेती है। इसे यहां लोग तेलपिया कहते हैं बाजार में यह निम्न कोटी की मछली मानी जाती है। इसकी कीमत अन्य मछलियों से कम होती है, इस कचड़ा एवं शैवाल भक्षी मछली को स्वास्थ्य के लिये भी खराब माना जाता है।

बख्श दिजिये सौंदर्यीकरण से

रांची में जितने भी तालाब आज सौंदर्यीकरण के बाद जलरहित हैं, वहां गौर करने लायक बात है कि, उन तालाबों में कंक्रीट का उपयोग खूब हुआ है। डिस्टिलरी तालाब , जोड़ा तालाब, करमटोली तालाब, लाइन तालाब में कंक्रीट से पक्की दीवार ढाल कर उसके प्राकृतिक जलप्रवाह को खत्म कर दिया गया है।इससे तो बेहतर होता कि सरकार सौंदर्यीकरण के बजाय तालाबों को साफ सफाई करके बख्श देती।

ट्रांसफर्मर तालाबः जिसके पानी में आग लग जाती है।

चुटिया स्थित ट्रांसफर्मर तालाब भी अपने प्रदूषण के कारण चर्चा में रहा। छठ के लिये इस तालाब की साफ सफाई की गयी इस दरम्यान इसके सतह पर तेल की परत देख किसी ने माचिस जला कर देखा तो पानी में आग लग गयी। बिजली विभाग इस तालाब में ट्रांसफर्मर रिपेयरिंग का तेल बहा देता है, अब इसका अस्तित्व खत्म है ,इसमें ज्वलनशील पदार्थ की मात्रा बढ़ गयी है, और पानी में आग लग जाती है।

नौनिहालों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना लक्ष्यःमुख्यमंत्री

- जन चौपाल महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार टेक होम राशन वितरण योजना एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुफ्त रसोई गैस चूल्हा वितरण का शुभारंभ
- पूरे राज्य में सखी मंडल की महिलाएं आंगनबाड़ी के लिए तैयार करेंगी "रेडी टू ईट"

संवाददाता

खूंटपानी, प.सिंहभूमः झारखंड के नौनिहाल हष्ट पुष्ट हों, उन्हें पौष्टिक भोजन मिले यह राज्य सरकार का लक्ष्य है। साथ ही महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो। इस निमित्त अब आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट की आपूर्ति सखी मंडल की बहने करेंगी। इसका शुभारंभ आज खूंटपानी से हो रहा है। आनेवाले दिनों में पूरे राज्य में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे पूर्व रेडी टू ईट की आपूर्ति दिल्ली की एक कंपनी द्वारा किया जाता था। अब सखी मंडल की बहनें इसकी आपूर्ति करेंगी और 500 करोड़ रुपये हमारे झारखंड में ही रहेगा। जो नारी सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पश्चिमी सिंहभूम के खूंटपानी प्रखंड स्थित कुम्हार टोला में आयोजित जन चौपाल में कही।

400 बच्चों को देंगे मेडिकल व इंजीनियरिंग की कोचिंग

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 400 बच्चों को चिन्हित कर उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जाएगी। ताकि झारखंड के आदिवासी, दलित और वंचित समाज के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार से जुड़ सकें। कोल्हान के सभी प्रखंड में कौशल विकास केंद्र खोलने की योजना है। युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से आच्छादित करना है। मैंने भी मजदूरी की है और गरीबी क्या होती है इसका मुझे अनुभव है। आज केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाएं गरीबों के लिए है। सरकार की सोच गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना है। आने वाले दिनों में राज्य के सभी बीपीएल कार्डधारी परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है।

बीएयू के कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि फॉल आर्मी वर्म के प्रकोप से मकई फसल में सावधानी की जरूरत

अमेरिका से आया फॉल वर्म कीड़ा मकई फसल के लिये बना खतरा

ग्रामीणों को फॉल वर्म की जानकारी देते बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक

संवाददाता

रांची :वर्तमान में अमेरिका से आया कीड़ा फॉल आर्मी वर्म के प्रकोप से मकई फसल की खेती से जुड़े किसानों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसका प्रकोप झारखंड सहित देश के सभी राज्यों में देखा जा रहा है। वर्षा अवधि में ज्यादा विलम्ब होने और वातावरण में ज्यादा नमी से फॉल आर्मी वर्म कीट को बढ़ने का पर्याप्त अनुकूल माहौल मिल जाता है। यह कीट मकई के पौधे को बढ़ने से रोकता है और यदि समय पर इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरा पौधा ही चट कर जाता है। कुलपति डॉ आरएस कुरील ने कहा कि इस कीट का सर्वाधिक प्रभाव मक्के की फसल पर होता है। चूंकि मक्का राज्य का एक प्रमुख खरीफ फसल है एवं इसका क्षेत्रफल .....शेष पेज 3 पर

कीट वैज्ञानिक डॉ मिलन कुमार चक्रवर्ती और पौधा रोग वैज्ञानिक डॉ एमके वर्णवाल ने कहा कि इस प्रकोप का जैविक विधि से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को देशी गाय के गोमूत्र में नीम की पत्ती को 4-5 दिनों तक सड़ा लेना चाहिये। इसके घोल को छान कर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिये। यह छिड़काव मकई फसल के घुटने तक लंबाई पर करनी चाहिये। इस विधि से छिड़काव करने पर पहली बार ही प्रकोप से राहत मिल जाती है। फसल पर इस कीट का अधिक प्रकोप होने पर ही बाजार में उपलब्ध रासायनिक दवा का प्रयोग करना चाहिये।

मेकॉन को राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार

नई दिल्ली, एजेंसियां: विज्ञान भवन मे आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन और कॉर्पोरेट मामलात राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में भारत सरकार के संस्थान मेकॉन लिमिटेड को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सीएसआर के लिए ''123 सीएसआर सम्माननीय उल्लेख'' से सम्मानित किया गया । यह पुरस्कार मेकॉन के सीएमडी अतुल भट्ट को दिया गया । इस अवसर पर निदेशक तकनीकी पी के सारंगी व कार्यकारी निदेशक संजीव कुमार भी मौजूद रहे। मेकॉन ने रांची स्थित गाँव पाँचा के बार टोली मे ''सोलर फोटोवोल्टिक आधारित पेयजल सिस्टम परियोजना'' के तहत पीने के पानी के लिए बोरवेल व सौर ऊर्जा चालित पंप सेट व ऊंचाई पर टंकी (ओवरहेड टैंक) गाँव के केंद्रीय स्थान पर स्थापित कर इस इलाके के निवासियों के लिए पीने के पानी के लिए सुविधा मुहैया की है । मेकॉन की इस पहल से, ग्रामीणों को गाँव में सुलभ स्थान पर चौबीसों घंटे स्वच्छ पीने योग्य पानी उपलब्ध हो रहा है व पानी पूर्णतः बैक्टीरिया के संक्रमण से मुक्त है । इससे पहले इस इलाके के लोग घने जंगलों के बीच अंधेरे मे पानी लेने जाते थे। गौरतलब है कि, मेकॉन ने गांव पाँचा को गोद ले रखा है । और यहाँ पर बुनियादी सुविधा मुहैया हो , इसके लिए मेकॉन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व समावेशी और सतत विकास के तहत हर संभव प्रयास कर रहा है। मेकॉन ने सीएसआर परियोजना के माध्यम से ग्रामीण विकास से संबन्धित सीएसआर गतिविधियों मे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, आजीविका, सामुदायिक बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास के तहत कार्यक्रम शामिल है ।

प्रदूषण दिल्ली का तेंदूआ पराली के धुएं से भाग गया होगा?

मनोज कु. शर्मा

कुछ साल पहले यमुना के आस पास हरियाली और सघन पेड़ पौधों को देख वहां कहीं से एक तेंदूआ भटक कर आ गया था, प्रकृति प्रेमियों ने इस पर खुशी जताई और दिल्ली के आबोहवा को सुधरता हुआ बताया। अब आज ये सवाल उठता है कि वो तेंदूआ है या भयंकर प्रदूषण देख कर वहां से पलायन कर गया होगा?

दिल्ली में भयंकर प्रदूषण के कारण इमर्जेंसी है और राजनीति का मौका भी। विजय गोयल उपवास पर बैठे। किसके खिलाफ उपवास पर बैठे हैं? क्या केजरीवाल इतना धुंआ उगल रहे हैं या पराली जला रहे हैं। दूसरी ओर ऑड इवेन में निदान खोजने वाले केजरीवाल दिल्ली के बच्चों से आग्रह कर रहे हैं कि वो पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर पराली जलाने पर रोक की मांग करें। वहीं हरियाणा के भाजपाई बोल रहे हैं कि हरयिाणा में पराली नहीं भी जलायें फिर भी दिल्ली की हवा प्रदूषित ही रहेगी। सबके पास कुतर्कों की भरमार है, निदान किसी के पास नहीं है।

कभी दिल्ली के आसमान से गुजरने वाले हवाई यात्री नीचे बाग बगीचों , हरियाली को देखकर इसे गार्डेन सिटी कहते थे। आकाश से भी साफ दिखने वाला ये शहर अब जमीन पर भी धुंध और प्रदूषण के चलते नहीं दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली अब दिलवालों की नहीं खराब फेफड़े वालों की है। और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक का शर्मनाक तमगा लिये हुये है।

दिल्ली का एक्यूआई 900 से ऊपर है। यह धुंध वाली तस्वीर सर्वप्रिय और प्रसिद्ध साहित्यकार उदय प्रकाश ने दिल्ली स्थित अपने आवास के बालकनी से शूट कर ग्रीन रिवोल्ट को दी है।

आपने क्रिकेट मैच बारिश के कारण मैदान गीला होने से, दर्शकों के हुड़दंग से, बिजली गुल होने से या खिलाड़ियों के बहिष्कार के कारण तो रूकते देखा होगा लेकिन दिल्ली में मैच प्रदूषण के कारण कम विजिबिलिटी से भी रूकता है। यह शर्मनाक कारण कुछ सालों पहले दिल्ली में देखने को मिला था। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा कितनी प्रदूषित है। आज हालत ये है कि, दिल्ली में पांच नवंबर तक प्रदूषण के कारण स्कूल बंद कर दिये गये हैं और लोगों को खुले में सैर करने और व्यायाम करने से मना कर दिया गया है। ये सब कोई एकाएक दीपावली के पटाखों के कारण नहीं हुआ है। हकीकत में तो दिल्ली लंबे समय से इन सब का शिकार है और प्रदूषण से निबटने के लिये जो प्रयास किये गये वो नाकाफी है। सालों पहले मुख्य शहर से सभी फैक्ट्रियों को कोर्ट के आदेश से बाहर शिफ्ट किया गया, सीएनजी ऑटो और बसें चलवायी गयीं, लेकिन यह सब समस्या से निबटने के लिये नाकाफी थे।

आखिर दिल्ली क्यों है इतनी प्रदूषित?

सबसे ज्यादा धुंध और धुंआ पंजाब और हरियाणा के किसानों के पराली जलाने से हुआ है। ये मामला एक प्रहसन बन कर रह गया है।पंजाब हरियाणा के किसान फसल कटने के बाद उसके पराली को खेतों में ही जलाते हैं और इसका धुंआ दिल्ली के आकाश में छा जाता है। इस कारण को जानने के बाद भी लंबे समय से इसपर सिर्फ चर्चा होती रही लेकिन किसी भी सरकार ने पराली जलाने पर रोक नहीं लगाई। सिर्फ बहस, किसानों से आग्रह तक ही बातें सिमट कर रह गयीं। पराली से कप प्लेट दोना बनाने की बात और तकनीक पर चर्चा तो होती है लेकिन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। दिल्ली के आसमान में हर साल इस मौसम में पराली का धुंआ छाया रहता है। अभी दिल्ली में प्रदूषण का आधा कारण यही पराली जलाने से है। इसके अलावा दिवाली पर पटाखों का धुंआ, वाहनों का धुंआ दिल्ली की हवा को जहरीला बनाये हुये है और बांग्लादेशी क्रिकेटर मैदान में मास्क पहन कर नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ●

सीएमपीडीआइ में मनाया गया कोल इंडिया का स्थापना दिवस

संवाददाता

रांची :मिनी रत्न कम्पनी सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया स्थापना दिवस-2019 समारोह 1 नवंबर को मनाया गया। निदेशक (तकनीकी/ईएस)के0के0 मिश्रा ने कोल इंडिया के झंडे को फहराया और इसकी शुरूआत कॉरपोरेट गीत से हुई। इस मौके पर संस्थान के निदेशक (तकनीकी/पीएंडडी) ए0के0 राणा, जेसीसी सदस्य, सीएमओएआई के प्रतिनिधि के अलावा सीएमपीडीआई परिवार के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। के.के. मिश्रा ने कहा कि स्थापना काल नवम्बर, 1975 में कोल इंडिया का उत्पादन स्तर लगभग 79 मिलियन टन (एमटी) से कई गुणा बढ क़र 2018-19 में 607 मिलियन टन हो गया । सीएमपीडीआई ने कोल ब्लॉकों की पहचान से लेकर विस्तृत गवेषण, प्रोजेक्ट प्लानिंग, पर्यावरण तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोल इंडिया स्तर पर सीएमपीडीआई को 6 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर सीएमपीडीआई के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों को भी संस्थान के निदेशक के0के0 मिश्रा ने सम्मानित किया गया जिन्होंने वर्ष 2018-19 में बेहतरीन शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की है। इनमें दसवीं कक्षा के दिवजोत सिंह, रायमा बनर्जी, श्रेया गुप्ता, रिससाभ सिन्हा, इशा उत्कर्षानी ,रेयान शाहिद, रित्तिका दासगुप्ता एवं अनुभूति अमोल शामिल हैं।

निराशाजनक है तस्वीर

छठ महापर्व संपन्न हो गया। झारखंड की राजधानी की छठ इस बार दो मायनों में चर्चित रही। पहली कि शहर के बीचोबीच स्थित लाइन तालाब में छठ के तीन दिन पूर्व प्रदूषण के कारण हजारो मछलियां मर गयी और आस पास दुर्गंध फैल गया और दूसरी कि चुटिया में एक तालाब में माचिस मारते ही पानी में आग लग गयी? ऐसा इसलिये कि उस तालाब में बिजली विभाग के कर्मियों ने ट्रांसफर्मर का इतना तेल बहा दिया है कि पानी के ऊपर उसकी एक परत बन गयी है। दोनो ही वाकये एक निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। मार्के की बात है कि, लाइन तालाब में मछलियों के मरने का वाकया पहले भी हो चुका है। और इस तालाब के सौंदर्यीकरण पर अच्छी खासी रकम फूंकी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री के एकल प्लास्टिक पर रोक के आह्वान का कोई असर जनता में नहीं है। पर्व त्यौहारों में हम धड़ल्ले से प्लास्टिक के ग्लास और दोने का उपयोग कर उन्हें बाहर सड़क फेंक रहे हैं। सरकार का प्लास्टिक पर बैन एक रस्मि आदेश होकर रह गया है। सड़क पर दूकानदार प्लास्टिक बैग में ही सामान दे रहे हैं उन्हें अपने ग्राहकों को नाराज नहीं करना है और पढे लिखे लोग भी प्लास्टिक कैरी बैग की मांग कर रहे हैं। उससे भी बुरी हालत तो अब तालाबों और नदियों की होंगी, पर्व त्यौहारों के समापन के बाद विसर्जन की सारी चीजें प्लास्टिक कैरी बैग में ठूंस कर लोग तालाबों नदियों में फेंक जाते हैं। ये सब उन्हीं घाटों पर हो रहा है जिसे हाल ही में साफ किया गया है और आस्था से पर्व मनाया गया है। ये हम भारतीयों की फितरत है कि हर लापरवाही और नुकसानदेह कृत्य को ढोते हैं और दूसरों से पहल की उम्मीद करते हैं। साफ सफाई, पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकारों के भरोसे संभव नही हो सकता। सरकारें किसी जगह को तालाब को नदी को एक बार पूरे अमले को झोंक कर साफ करवा सकती हैं, लेकिन उस व्यवस्था को बरकरार रखना आम जन का काम है। किसी जगह को सबसे ज्यादा प्रदूषित आम जन करता है, सरकारी तंत्र नहीं करते। और ये निराशाजनक तस्वीर हम आप ही बदल सकते हैं, अकेले सरकारें नहीं।

> झारखंड के विभिन्न शहरों का प्रदूषण स्तर इतना बढ गया है कि यहां के आम आदमी की जिंदगी चार से पांच साल घट गयी है। छठ जैसे महापर्व में जो कि विश्व को पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम का संदेश देता देता है। खरना के प्रसाद खीर को परोसने से लेकर पानी देने तक के लिये उन्हीं प्लास्टिक और थर्मोकोल के दोने और ग्लास का उपयोग हर जगह दिखा जिसके उपयोग पर हम दिन रात भाषण देते हैं । अक्टूबर 2019 में ये आह्वान किया गया है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। आश्चर्य कि इसे पर्यावरण विरुद्ध तो सभी कहते हैं फिर भी इसके उपयोग से किसी को परहेज नहीं है।

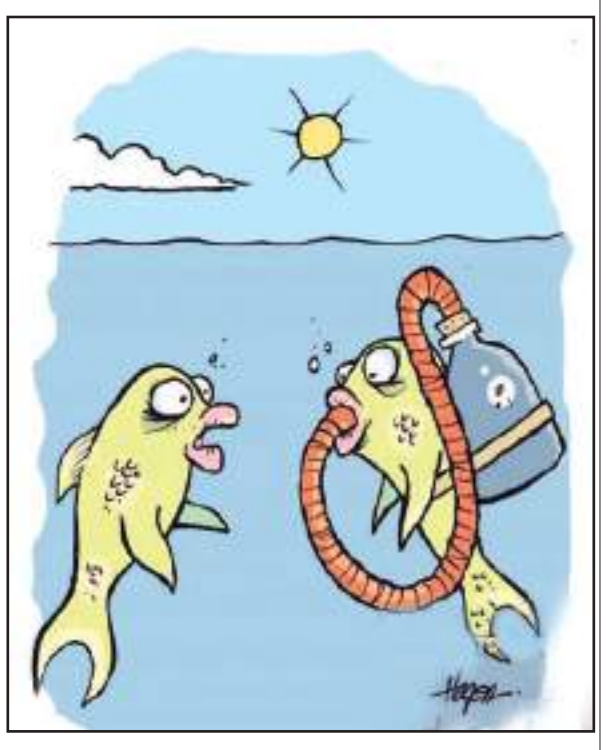

पराली और प्रदूषण

आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। सरकार के कई कदम उठाने के बावजूद किसानों ने पराली जलाने से कोई परहेज नहीं किया। इसका नतीजा हम वायु प्रदूषण सूचकांक में देख सकते हैं जिसमें मंडी गोबिंदगढ़, जालंधर और लुधियाना जैसे शहरों की हवा सबसे प्रदूषित पाई गई है। इस हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है क्योंकि उसने तो किसानों को बेहद सख्त तरीके से समझाया पर किसान हैं कि माने नहीं। यह जानकर भी कि पराली जलाने का असर हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा, वे नहीं रुके और अपनी जिद पर अड़े रहे। अब सरकार की प्रदूषित वायु को शुद्ध करने की चिंता दीवाली के पटाखों पर रुकती है। पर क्या सिर्फ पटाखों को रोकने या उन्हें फोड़ने का समय तय कर देने भर से वायु को साफ किया जा सकता है? 365 दिन की समस्या को सिर्फ एक दिन के प्रतिबंध से काबू नहीं किया जा सकता है इसलिए सरकार को ऐसा हल ढूंढ़ना चाहिए जो लंबे सफर का साथी हो।

15 साल में दोगुनी गति से पिघले हैं हिमालय के ग्लेसियर्स

मिहिर शाह

हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो कि काफी चिंताजनक है। ग्लेशियरों की स्थिति पर हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि पिछले करीब दो दशकों से इनके पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो गई है। तापमान लगातार बढ़ने के कारण हिमालय के साढ़े छह सौ ग्लेशियर संकट में हैं। इस बारे में राज्यसभा में भी चिंता जताई गई है। कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने राज्यसभा में बताया कि सियाचिन और गंगोत्री सहित हिमालय क्षेत्र के करीब 10 हजार ग्लेशियर तेजी से और लगातार पिघल रहे हैं।

उपग्रह से किए गए सर्वेक्षण और एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 15 वर्षों में ग्लेशियरों के पिघलने की दर दोगुनी हुई है। यही वजह है कि हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के जल स्तर में वृद्धि हुई है और यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि आने वाले समय में इस वजह से जलसंकट भी बढ़ेगा। हिमालय के ग्लेशियरों पर ग्लोबल वॉर्मिंग के असर का आकलन करने वाली एक टीम ने पाया है कि साल 2000 से 2016 के बीच हर साल ग्लेशियरों की औसतन 800 करोड़ टन बर्फ पिघल रही है। इससे पहले के 25 वर्षों यानी 1975 से 2000 तक हर साल औसतन 400 करोड़ टन बर्फ पिघलती रही, लेकिन इसके बाद के डेढ़ दशक में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे हालात में ग्लेशियरों की पूरी हिमालयन रेंज कब तक पिघल जाएगी? और आने वाले समय में खतरनाक नतीजे क्या होंगे?

सात तरीकों से हो सकता है पृथ्वी का नुकसान

पृथ्वी की तस्वीरें खींचने के लिए अमेरिका ने 70 और 80 के दशक में जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। उनसे मिले चित्रों को थ्रीडी मॉड्यूल में बदलकर किए गए शोध के मुताबिक 1975 से 25 वर्षों तक हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर, हर साल 10 इंच तक घट रहे थे। वह 2000 से 2016 के बीच हर साल औसतन 20 इंच तक घट रहे हैं। साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित इस शोध रिपोर्ट के मुताबिक करीब 800 करोड़ टन पानी का नुकसान हर साल हो रहा है।

बढ़ा है हिमालय का तापमान

कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थ इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पाया है कि दो हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी पट्टी में फैले हिमालय क्षेत्र का तापमान एक डिग्री से ज्यादा तक बढ़ चुका है। इसकी वजह से ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो गई है। शोधकर्ताओं ने 40 वर्षों के इन उपग्रही चित्रों का अध्ययन नासा और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के ताजा डेटा के विश्लेषण के साथ किया तो पाया कि कैसे हिमालय क्षेत्र बदल रहा है और कैसे 650 ग्लेशियरों पर खतरा बढ़ रहा है।

80 साल में पिघल जाएंगे दो तिहाई ग्लेशियर

अगर ग्लोबल वॉर्मिंग के खतरे के मद्देनजर चलाए जा रहे ग्लोबल क्लाइमेट प्रयास नाकाम हुए तो साल 2100 तक हिमालय क्षेत्र के दो तिहाई ग्लेशियर पिघल चुके होंगे। इस खतरे की भयावहता को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लोबल वॉर्मिंग से निपटने के लिए जो महत्वाकांक्षी पेरिस समझौता हुआ, उसका लक्ष्य है कि इस सदी के आखिर तक ग्लोबल वॉर्मिंग को डेढ़ डिग्री तक सीमित किया जाए, लेकिन ऐसा कर पाने के बावजूद तब तक 2.1 तक डिग्री तापमान बढ़ चुका होगा।

इसका नतीजा ये होगा कि दो तिहाई तक हिमालयन ग्लेशियर पिघल चुके होंगे और एशिया के जिन इलाकों में इन ग्लेशियरों के कारण नदियां प्रवाहित होती हैं, उन पर निर्भर करने वाली करीब दो अरब लोगों की आबादी सीधे तौर पर जीवन संकट से जूझेगी। दुनिया के पर्यावरणविद् इस खतरे को भांप चुके हैं और वो इसे इस सूत्र के रूप में देखते हैं। इन सभी का मानना है कि यदि ग्लेशियर इसी रफ्तार से पिघलते रहे हो हिंदुकुश क्षेत्र के आठ देशों में हिमालयन सुनामी आ जाएगी। ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी होने के बाद आठ देशों के लिए खतरे की घंटी बजी है:

भारत,चीन,म्यांमार,नेपाल,अफगानिस्तान, पाकिस्तान,बांग्लादेश,भूटान। ये आठों देश हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में हैं। 650 ग्लेशियरों के खतरे में आने के बाद यहां के जनजीवन पर भारी असर पड़ने वाला है। केदारनाथ त्रासदी को भी हिमालयन सुनामी का एक रूप माना जा सकता है।

ग्लेशियर पिघलने से जुड़ी 2 खास बातें

ग्लेशियर पिघलने से ऊंची पहाड़ियों में कृत्रिम झीलों का निर्माण होता है। इनके टूटने से बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है जिससे ढलान में बसी आबादी के लिए खतरा उत्पन्न होता है।

नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड तथा कार्बन डाई ऑक्साइड जैसी गैसों का ग्लेशियरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए 'ब्लैक कार्बन' की उत्सर्जन दर की भी निगरानी की जानी चाहिए।

गंभीरता न बरती तो इन खतरों से निपटना होगा

ग्लेशियरों के पिघलने का सबसे पहला नतीजा होगा भयानक बाढ़। जैसा कुछ साल पहले हम केदारनाथ में देख चुके थे। इस–के दूरगामी नतीजे ये होंगे कि ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। डेढ़ अरब से ज्यादा की आबादी के लिए भोजन पैदा होने की समस्या होगी, तापमान बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा और ऊर्जा के कई साधन बहुत तेजी से ठप होते जाएंगे।

एक ब्रिटिश विशेषज्ञ का कहना है कि एक पीढ़ी के बदलने के दौरान ही ग्लेशियर दोगुनी तेजी से पिघलने लगे हैं। ये क्यों खतरे की घंटी है? बर्फ पिघलने का अंजाम ये होगा कि एशिया की नदियों में पानी नहीं रहेगा और सूखे के हालात बनने लगेंगे। ग्लेशियरों के पिघलने के कारण नदियों पर आश्रित करोड़ों की आबादी भयानक सूखे से जूझने के लिए मजबूर होगी।

प्रदूषण भी है ग्लेशियरों के पिघलने का कारण

वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वॉर्मिंग तो मुख्य कारण है ही, लेकिन एशियाई देशों में लकड़ी, कोयला बहुत अधिक मात्रा में जलाया जाता है। इसका धुआं सीधे आसमान में जाता है और साथ में कार्बन लेकर जाता है। इसी प्रदूषित धुएं के बादल जब पर्वतों के ऊपर छा जाते हैं, तब सोलर एनर्जी यानी सौर्य ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करते हैं। इनकी वजह से पर्वत पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। भारत, चीन, नेपाल, भूटान की 80 करोड़ आबादी निर्भर है ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों पर। इन नदियों से सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन किया जाता है। ग्लेशियर पिघल गए तो तमाम संसाधन खत्म हो जाएंगे। 60 करोड़ टन बर्फ जमी हुई है हिमालय के करीब 650 ग्लेशियरों में। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बाद यह तीसरा बड़ा क्षेत्र है जहां इतनी बर्फ है। इसलिए हिमालयी ग्लेशियर क्षेत्र को तीसरा ध्रुव भी कहते हैं।

हिमालय के निचले इलाकों में कई जगहों पर अध्ययन के अनुसार, एक साल में 16 फीट तक की बर्फ पिघल गई। 08 बिलियन टन पानी हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से नीचे आ रहा है। इतने में 32 लाख स्विमिंग पुल भर जाएं।

08 अरब टन पानी बर्बाद हो रहा है ग्लेशियर पिघलने से हर साल। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे कई छोटे द्वीपों पर खतरा बढ़ेगा।

खतरनाक है केदारनाथ मंदिर के ऊपर बन रही झील

पिछले कुछ समय से केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी में बन रही झील को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने उस झील का पता भी लगा लिया है। केदारनाथ मंदिर से करीब चार किमी ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर की तलहटी में एक पुरानी झील सदियों से अस्तित्व में थी, जिसे चौराबाड़ी झील के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां इस झील में विसर्जित किए जाने के बाद इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता था। 2013 में केदारनाथ और सम्पूर्ण केदारनाथ घाटी में हुए जल प्रलय के लिए इस झील में जमा पानी को ही मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। कहा जाता है कि तेज बारिश के कारण चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर चौराबाड़ी झील में गिर गया था, जिससे झील में सदियों से जमा पानी छलक कर नीचे की तरफ बहने लगा। पहाड़ी ढलान पर तेजी से बहते इस पानी ने केदारनाथ के साथ ही पूरी मंदाकिनी घाटी को तबाह कर दिया। 2013 की आपदा में चौराबाड़ी झील का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया था और यहां सिर्फ पत्थरों का रौखड़ बाकी रह गया था।

हर पल चेतावनी दे रही है प्रकृति

हेमंत कुमार पारीक

जीवन की खातिर पर्यावरण प्रेमी एक लड़की की आवाज पूरी दुनिया ने सुनी।

दिल्ली में मेट्रो चली तो उसका जोरशोर से स्वागत हुआ था। इसलिए भी कि दिल्ली की जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और नतीजतन, आवागमन के साधन अपर्याप्त हो गए थे। शहर की जरूरत के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन की काफी कमी थी। दिल्ली परिवहन निगम की बसें जनसंख्या का बोझ नहीं उठा पा रही थीं। आज देश के दूसरे शहरों और यहां तक कि राज्यों की राजधानियों का भी यही हाल है। रोजगार की तलाश में लोग हर रोज गांवों से पलायन कर शहर की तरफ आ रहे हैं। जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से आवागमन के नए-नए साधनों के विकास पर सरकार का ध्यान जा रहा है। लेकिन इसी क्रम में हरे-भरे पेड़ों को बेदर्दी से काटा जा रहा है। जनहित की आड़ में घने जंगलों की बलि दी जा रही है और जंगल मैदानों में तब्दील हो रहे हैं।

मुंबई की लोकल ट्रेन कई सालों से आबादी के इस बोझ से जूझ रही है। इसी प्रकार, कोलकाता की ट्रामें भी सालों से अपना कार्य सुचारु रूप से कर रही हैं। लेकिन जब दिल्ली की मेट्रो राजनीति के गलियारों में 'दूध देती गाय' नजर आई, तभी से बिना सोचे समझे, पर्यावरण की हानि का जायजा लिए बगैर मेट्रो प्रोजेक्ट को देश के दूसरे राज्यों, शहरों और राज्यों की राजधानियों में हरी झंडी दिखाई जाने लगी है।इसी के चलते जयपुर और लखनऊ में मेट्रो का पदार्पण हुआ। मुंबई में मेट्रो परियोजना काम कर रही है। इसी परियोजना के चलते आरे कॉलोनी सुर्खियों में आई। वहां करीब दो-तीन हजार पेड़ों की बलि दी जाने वाली थी। लेकिन वहां की पर्यावरण प्रेमी जागरूक जनता को समझ में आया तो चारों तरफ से आवाज उठने लगी। कई समाजसेवी संस्थाएं और फिल्मी हस्तियां आगे आईं और विरोध में उठ खड़ी हुईं। एक जागरूक समाज अपने वर्तमान के साथ-साथ अपने भविष्य के लिए भी जतन करता है।

हाल ही में स्वीडन की एक लड़की ग्रेटा थनबर्ग की ऐसी ही आवाज दुनिया की संसद में सुनाई दी है। उसने दुनिया भर के बड़े-बड़े राजनेताओं को चेतावनी दे डाली। पर्यावरण प्रेमी एक लड़की की आवाज पूरी दुनिया ने सुनी। कुछ ही दिनों पहले पर्यावरण को प्रभावित करने वाली दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली, अमेजन के जंगलों में लगी आग और दूसरी अंटार्कटिका के पिघलते हिमखंड। इन दोनों घटनाओं ने दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेजन के जंगलों को 'कार्बन सिंक' कहा जाता है। ये जंगल बहुत घने हैं। विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु यहां पाए जाते हैं और दुनिया भर की उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को ये वन सोख लेते हैं। यानी एक तरह से ये ओजोन परत को कार्बन डाइऑक्साइड से बचाने का महत्त्वपूर्ण काम करते हैं। इस कारण दुनियाभर के देशों के राजनीतिकों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। चूंकि अमेजन के जंगलों में लगी आग समूची दुनिया पर असर डालने वाली घटना है, इसीलिए सभी ने मिल कर आग पर काबू पाने के लिए अपने-अपने प्रस्ताव रखे। यह चिंता सकारात्मक है और पृथ्वी को बचाने के लिहाज से जरूरी है।

पर्यावरण से जुड़ी दूसरी घटना है दक्षिणी ध्रुव के बर्फीले अंटार्कटिका में एक विशाल हिमखंड का टूट जाना। पिछले पचास वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक 'लूज-टूथ' नाम के हिमखंड के पिघलने की चेतावनी पिछले कई सालों से दे रहे थे, पर यह दूसरा हिस्सा था, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह छोटा-मोटा हिमखंड नहीं था, बल्कि इतना विशाल था कि इसमें पूरी दिल्ली समा जाती। यही नहीं, इसके आकार के लिहाज से देखें तो इसमें दिल्ली से सटे गाजियाबाद और मथुरा भी निपट जाते। कुछ ऐसा ही ओकोजोकुल नामक हिमखंड के पिघलने का वाकया भी है। ये चेतावनियां हैं प्रकृति की, दुनिया में बढ़ते तापमान के लिए। अगर हम अब भी नहीं संभले और इसी गति से हिमखंड पिघलते रहे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर क्या होगा? इसका सीधा असर समुद्र के जलस्तर पर पड़ेगा। जलस्तर बढ़ेगा और फिर बड़े-बड़े भूखंड देखते ही देखते समुद्र में विलीन हो जाएंगे। इस वर्ष इतनी बारिश हमारे देश में हुई कि उसने पिछले सौ वर्षों में हुई बारिश के रिकार्ड तोड़ दिए। मानसून आया, पर जाने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि इसकी अवधि कब की समाप्त हो चुकी थी। बाढ़ ने उग्र रूप दिखाया, नतीजतन पटना जैसे शहर जलमग्न रहे। लोग हाल-बेहाल हुए। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। घर और बाजारों में नदी-नाले बह निकले। सड़कों पर नावें चलने लगीं। ऐसे में स्वीडन की उस लड़की ग्रेटा की चेतावनी पर ध्यान देने की जरूरत है। हर आदमी को पर्यावरण के विषय में सोचने की जरूरत है। जागरूक होने का वक्त है। जिस तरह आरे कॉलोनी के लिए आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड के सितारे पर्यावरण बचाने के पक्ष में सड़कों पर उतर आए थे, हमें भी पर्यावरण के संबंध में ग्रेटा के साथ खड़ा होना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।●

वायु प्रदूषण खत्म करने के लिए करने चाहिए ये काम

एक अध्ययन में कहा गया है कि घर डेवलपर्स, टाउन प्लानर्स और राजनेताओं को समझाया जाए तो वायु प्रदूषण को काबू किया जा सकता है ।इंग्लैंड के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कहा है कि यदि किसी भी शहर में बनने वाले घरों और इलाकों को सही से विकसित किया जाए तो वायु प्रदूषण के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। यह पेपर जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित हुआ है। इंग्लैंड की सर्वेयर यूनिवर्सिटी के ग्लोबल सेंटर फॉर क्लीन एयर रिसर्च (जीसीआरईआर) ने वायु प्रदूषण, ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर और मानव स्वास्थ्य आपस में किस तरह जुड़े हैं, इस पर तीन अलग-अलग क्षेत्रों में अध्ययन किए हैं। अध्ययन में कहा गया है कि घर बनाने वाले डेवलपर्स, शहरों की योजनाएं बनाने वाले प्लानर्स और राजनेताओं को इस बात की जानकारी होने चाहिए कि शहरों को इस तरह से बसाया जाए, जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो।

सर्वेयर विश्वविद्यालय में जीसीएआरई के निदेशक और प्रमुख अध्ययनकर्ता, प्रोफेसर प्रशांत कुमार ने कहा कि ब्रिटेन में हर साल 3 लाख घर बनाने की जरूरत है। दुनिया भर के लगभग सभी बड़े शहरों में हर साल नए घर बनाने का दबाव रहता है। ऐसे में, घरों को बनाने से पहले हमें उन डेवलपर्स और योजनाकारों को सूचीबद्ध करना होगा, जो घर बानाने के साथ-साथ वायु प्रदूषण, उसके प्रभावों को किस तरह कम किया जाए इस बारे में जानकारी रखते हो, उन्हें ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है इस बारे में जानकारी होनी चाहिए।

ग्लोबल वार्मिंग से युवाओं में कुपोषण

ग्लोबल वार्मिंग फसलों की उत्पादकता को कम कर देती है जिसके चलते कुपोषितों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पर क्या तापमान में होने वाली वृद्धि सीधे तौर पर कुपोषण की दर को प्रभावित कर सकती है, यह अब तक ज्ञात नहीं था। ओपन एक्सेस जर्नल प्लॉस मेडिसिन में छपे अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के चलते कुपोषण और उससे होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। जिसके अनुसार गर्म मौसम के दौरान, दैनिक तापमान में हर एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, अस्पताल में कुपोषण के कारण भर्ती मरीजों की संख्या में 2.5 फीसदी की वृद्धि कर देती है।यह अध्ययन युवाओं और बुजुर्गों को गर्मी के जोखिम से बचाने के लिए बेहतर रणनीतियां बनाने की भी बात करता है।

केंद्र शासित प्रदेश लेह को अब कैसा विकास चाहिए?

सकारात्मक बदलाव की संभावना है, पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का डर भी

पंकज चतुर्वेदी

लेह को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कई सकरात्मक बदलाव की संभावना तो है, पर वहां के पर्यावरण को स्थायी नुकसान पहुंचने का डर भी है। कायनात की खूबसूरत देन वहां सदियों तक बाहरी प्रभावों से बची रही, क्योंकि बाहरी आदमी के लिए वहां तक पहुंचना दूभर था। फिर पर्यटन व्यवसाय बन गया, हवाई जहाज आने-जाने लगे, पांच-पांच दर्रे पार कर मनाली से सड़क निकाल दी गई।

ईंधन चालित वाहनों ने धरती के इस अनछुए हिस्से पर अपने पहियों के निशान बना दिए। आधुनिकता आई, पर वही आधुनिकता आज उनकी त्रासदी बन रही है। आधुनिकता के साथ सीमेंट, लोहा बेचने वाली कंपनियां भी आईं। पर स्थानीय लोगों का दो दशक में ही कंकरीट से मोहभंग हो गया है। स्थानीय मिट्टी और रेत से बने पारंपरिक मकान लौट रहे हैं।

कुछ दशक पहले तक लेह-लद्दाख के दूर-दूर बसे बड़े से घरों के छोटे-छोटे गांवों में करेंसी का महत्व गौण था। अपना दूध-मक्खन, अपनी भेड़ के ऊन के कपड़े, अपनी नदियों का पानी और अपनी फसल। न चाय में चीनी की जरूरत थी, न मकान में फ्लश की। पर सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा दिया और कुछ होटल बने, तो देखादेखी कुछ लोगों ने ईंट और सीमेंट से आधुनिक डिजाइन के मकान खड़े कर लिए, ताकि बाहरी लोग उनके मेहमान बनकर रहें, जिससे कमाई हो। घर-घर नल भी पहुंच गया। वहां ठंड के दिनों में औसतन प्रति व्यक्ति 10 लीटर व गर्मी में अधिकतम 21 लीटर पानी की जरूरत होती थी।

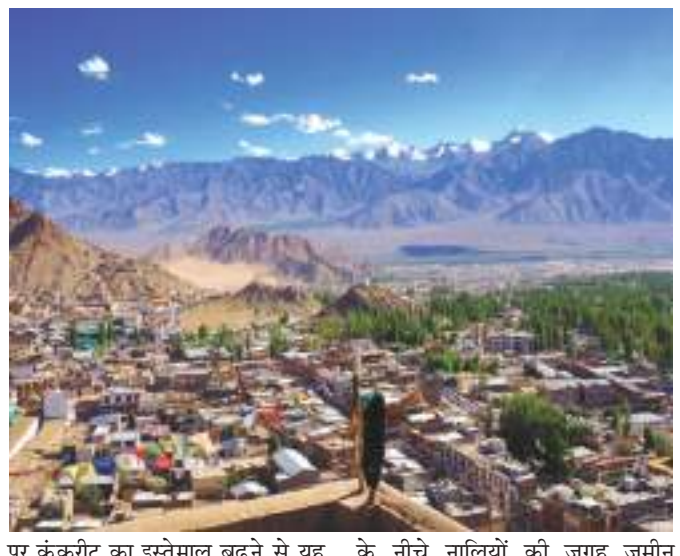

पर कंकरीट का इस्तेमाल बढ़ने से यह मांग औसतन 75 लीटर तक हो गई। अब पहाड़ों की ढलानों पर बसे मकानों के नीचे नालियों की जगह जमीन काटकर पानी तेजी से नीचे आने लगा, जिससे पारंपरिक और आधुनिक मकान ढहने लगे। ज्यादा पैसा बनाने के लोभ में जमीनों पर कब्जे और दरिया किनारे पर्यटकों के लिए आवास की प्रवृत्ति बढ़ी। वहां सैकड़ों ऐसी धाराएं है, जहां सालों पानी नहीं आता, पर जब ऊपर ज्यादा बर्फ पिघलती है, तो अचानक तेज जल-बहाव होता है। लेह-लद्दाख में पहले बरसात कम होती थी, पर जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मियों में कई बार बरसात होती है। पर्यटन बढ़ने से कचरा बढ़ा, जेनरेटर जैसे धुआं उगलने वाले यंत्र का इस्तेमाल भी बढ़ा। वहां ऊपरी इलाकों में पशुपालक और निचले हिस्से में किसान रहते हैं। स्थानीय मिट्टी में रेत मिलाकर धूप में पकाई गई ईंटों से बने इनके पारंपरिक घरों की बाहरी दीवारों को स्थानीय 'पुतनी मिट्टी' व उसमें वनस्पतियों के अवशेष को मिलाकर ऐसा कवच बनाया जाता है, जो शून्य से नीचे तापमान में भी उसमें रहने वालों को उष्मा देता है। यह इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील तो है ही। ऐसे में पारंपरिक आवास सुरक्षित माने जाते रहे हैं। सीमेंट की वैज्ञानिक आयु 50 साल है, जबकि पारंपरिक तरीके से बने अनेक मकान, मंदिर और मठ हजार साल से खड़े हैं। यहां के पारंपरिक मकान तीन मंजिला होते हैं, जिनमें सबसे नीचे मवेशी और उसके ऊपर परिवार रहते हैं, तो सबसे ऊपर पूजा घर होता है।

बाहरी दुनिया के हजारों लोग अपने पीछे इतनी गंदगी और आधुनिकता की गर्द छोड़कर जा रहे हैं कि स्थानीय समाज का अस्तित्व खतरे में हैं। बाहरी दखल के चलते यहां अब चीनी का इस्तेमाल होने लगा, जिससे स्थानीय समाज में डाइबिटीज जैसे रोग घर कर रहे हैं। पर्यटन को पूरी तरह बाधित किए बगैर स्थानीय समाज को उनके पारंपरिक जीवन मूल्यों के बीच रहने देने की व्यवस्था करना ही इस समस्या का समाधान है।●

ग्रीन हेजिंग से घेराबंदी का आदेश

रांची: मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने नगर विकास विभाग को रांची स्मार्ट सिटी की घेराबंदी ग्रीन हेजिंग (तार या प्लास्टिक की जालीदार दीवार जिसपर हरी पत्तियों वाले लत्तर चढ़ते हैं) से करने का निर्देश दिया है। वहीं वन विभाग को भी प्रयोग के तौर पर हवाई अड्डा से लेकर प्रोजेक्ट भवन के बीच कहीं प्रयोग के तौर पर सड़क किनारे ग्रीन हेजिंग का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धूल कणों के प्रसार को रोकने का यह प्राकृतिक तरीका पर्यावरण की सुरक्षा के साथ सुंदरीकरण का भी मॉडल बन सकता है। इसी तरह की ग्रीनवॉल धनबाद एवं अन्य शहरों में बनाई जाये, जहां की वायु में 2.5 तथा 10पीएम के कणों की मात्रा मानक से काफी अधिक है और आम जन वायु प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न आवासीय क्षेत्रों/कॉलोनी तथा प्रदूषित क्षेत्र जैसे खनन कार्य क्षेत्र, निर्माण कार्य क्षेत्र, बड़ी सड़कों के यातायात के क्षेत्र आदि के मध्य ग्रीनवॉल बनाकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की संचालन समिति की बैठक में बोल रहे थे।

मेकॉन में ''रन फॉर यूनिटी'' का आयोजन

राष्ट्रीय एकता दिवस यानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मेकॉन लिमिटेड ने 31 अक्टूबर को ''रन फॉर यूनिटी'' का आयोजन जेवीएम श्यामली स्कूल से ई ब्लॉक पार्क तक किया गया । इस कार्यक्रम का शुभारंभ मेकॉन के सीएमडी अतुल भट्ट द्वारा किया गया । इस कार्यक्रम मे सीवीओ यू के केडिया, कार्यकारी निदेशक(सीएस) संजीव कुमार, कार्यकारी निदेशक (टीएस) सीडी गोस्वामी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जेवीएम श्यामली के प्रधानाचार्य समरजीत जना व स्कूल के बच्चों ने भाग लिया । सीएमडी अतुल भट्ट ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन दी और एकता व अखंडता की मिसाल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से आदर्शो के साथ बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया ।

संत एंथोनी स्कूल में निबंध एवं नारा लेखन प्रतियोगिता

रांची संवाददाता :सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 के दौरान संस्थान के सतर्कता विभाग द्वारा संत एंथोनी स्कूल, डोरण्डा, रांची में ''ईमानदारी-एक जीवन शैली'' विषय पर निबंध और नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वर्ग 9 एवं 10 के लगभग 100 बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता में तथा कक्षा 8 के लगभग 50 छात्र/छात्राओं ने नारा लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान स्कूल के प्राचार्य सी0ए0 फ्रांसिस, सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक (सतर्कता) पुष्कर, मुख्य प्रबंधक आलोक कुमार त्रिपाठी एवं संजय कुमार ठाकुर, सहायक प्रबंधक श्रीमती रितु सिंह, अपराजिता दास, नंदलाल प्रसाद उपस्थित थे। संत एंथोनी स्कूल के वरीय शिक्षिका श्रीमती सीता राणा ने दोनों प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

खरना के दिन जमशेदपुर को मिला पाइपलाइन गैस आपूर्ति का उपहार

- मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय जनजातिय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जमशेदपुर में पाइप लाइन के जरिए गैस पहुंचाने की योजना का शुभारंभ
- जमशेदपुर शहरी गैस वितरण परियोजना अंतर्गत प्राइड फ्यूल, मानगो स्थित सीएनजी स्टेशन एवं आशियाना गार्डन सोसाइटी, सोनारी में पीएनजी आपूर्ति का उदघाटन
- पुरुलिया-जमशेदपुर प्राकृतिक गैस स्परलाइन का कार्य प्रारंभ एवं बरही स्थित एचपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास हुआ।
- Ease Of Life के तहत जनता तक सीधे सुविधा पहुंचे यह है सरकार का प्रयास
- गैस पाइपलाइन योजना गांव तक जाएगी : मुख्यमंत्री झारखण्ड
- सरकार की प्राथमिकता जनता से जुड़े मामलों को धरातल पर उतारना: अर्जुन मुंडा
- नया झारखण्ड बनाने को हम कृतसंकल्पित -धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री

संवाददाता

बिष्टुपुर/जमशेदपुर: केंद्र और राज्य सरकार का सपना है। "ईज ऑफ लाइफ" के तहत जनता तक सीधे सुविधा पहुंचे। उसी निमित आज जमशेदपुर शहरी गैस पाइप लाइन आपूर्ति योजना का शुभारंभ हुआ। यह योजना गांव तक जाएगी, जिस तरह लोगों को घरों में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पेयजल की आपूर्ति की जाती है। उस तरह गैस की आपूर्ति को भी सुनिश्चित करने की हमारी परिकल्पना अब यथार्थ रूप ले रही है। इससे पूर्व रांची में योजना का शुभारंभ हो चुका है। आने वाले दिनों में सिलेंडर की जरूरत लोगों को नहीं होगी। क्योंकि घर-घर पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति को हम सुनिश्चित करेंगे। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में शहरी गैस वितरण परियोजना के उद्घाटन, पुरुलिया जमशेदपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन योजना के कार्य प्रारंभ एवं बरही स्थित एचपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में कही। मुयख्मंत्री ने कहा कि गैस आपूर्ति योजना पेट्रोलियम मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने त्वरित गति से जमीन उपलब्ध कराते हुए योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने में अपना भरपूर सहयोग दिया है, जिसका परिणाम अब हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है और हम इस-के गवाह बन रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और राज्य की जनता को प्रदूषण रहित ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 8 करोड़ लोगों को योजना से लाभान्वित किया गया। झारखंड में 40 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिला। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो योजना के तहत चूल्हा व रिफिल भी मुफ्त उपलब्ध कराता है। केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वी भारत को बदलने का संकल्प लिया है। 2019 से 2024 का संकल्प नए भारत गढ़ने का है। हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करेंगे। गैस पाइपलाइन के माध्यम से जमशेदपुर के मानगो, सोनारी क्षेत्र में लोगों को गैस उपलब्ध होगा । अब शहर के साथ-साथ गांव को भी इन योजनाओं से जोड़ने की परिकल्पना को साकार रूप दिया जाएगा। इससे समय, ईंधन और राशि की बचत भी होगी। अगर हमें प्रदूषण रहित ईंधन प्राप्त होगा तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जमशेदपुर की पहचान औद्योगिक केंद्र के रूप में है। सरकार ने इसे और आधुनिक बनाने का प्रयास किया है। आज पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू ईंधन पहुंचाने का शुभारंभ हुआ। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में भी गैस पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जाएगी। ऑटो, छोटे वाहन, बसों में सीएनजी के उपयोग से एक स्वच्छ और प्रदूषण रहित ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। यह सस्ता है। एक ऑटो चालक सीएनजी चला कर 3 से 5 हजार रुपये की बचत कर सकता है। जो बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड अपार संभावना का क्षेत्र है।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर 141 बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सजा काट चुके बंदियों को भी सामान्य जिंदगी जीने का पूरा हक़ है। उन्होंने जाने-अनजाने जो गलती की थी, उसकी सजा उन्हें मिल गई है। अब उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना समाज के हर व्यक्ति का काम है। कोई भी व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जीये यह हक उसे हमारा संविधान प्रदान करता है। उक्त बातें उन्होंने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि कई सारे मामले ऐसे भी सामने आते हैं, जिसमें बंदी सजा काट लेते हैं, सजा पूरी हो जाती है लेकिन गरीबी के कारण कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं होने से वे बरी होने से वंचित हो जाते हैं। हर 3 माह में पर्षद की बैठक कर ऐसे मामलों का तुरंत निपटारा करें। आज की बैठक में कुल 153 मामलों पर चर्चा हुई। एक-एक कर सभी मामलों पर विस्तार से बातचीत हुई। इसके बाद 141 बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी।बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, डीजीपी कमल नयन चौबे, कारा महानिरीक्षक शशि रंजन समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

अमेरिका से आया फॉल वर्म

.....पेज 1 का शेष

और बढ़ने की संभावना है। अतः इस कीट का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। कीट की गंभीर अवस्था में सामान्य रूप से प्रचलित कीटनाशक इसके ऊपर ज्यादा प्रभावी नहीं है। अतः समन्वित प्रयासों के तहत इसका निदान किया जाना जरूरी है। मकई फसल पर आये इस नये प्रकोप से बचाव का बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निदान ढूढी है इस बीमारी के प्रकोप एवं निदान हेतु वैज्ञानिकों ने रांची जिले के चान्हो एवं मांडर में किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत दोनों प्रखंडो के कंजगी, कुल्लू, मुरमा, सुरसा, चुटियो एवं सर्कपदा गाँवो में एक दिवसीय प्रशिक्षण चलाया गया।

प्रशिक्षण में बीएयू के वैज्ञानिक डॉ मणिगोप्पा चक्रवर्ती, डॉ सीएस सिंह, डॉ मिलन कुमार चक्रवर्ती और डॉ एमके वर्णवाल ने किसानों को जैविक खेती के तकनीकों और लाभ की जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने विभिन्न फसलों में नये - नये कीट एवं रोग से बचाव के लिए जैविक खेती को अपनाने पर बल दिया। मौके पर वैज्ञानिकों ने बताया कि फॉल आर्मी वर्म नामक कीट मकई फसल के पत्तियों एवं गाभा को पूरी तरह नष्ट कर देता है। रात्रि में यह कीट 20 किलो मीटर तक की दूरी तय कर लेता है। बरसात में यह कीट तत्काल ख़त्म हो जाता है। वर्षपात की अवधि में लम्बे गैप से इसका प्रकोप बढ़ जाता है। पौधा रोग वैज्ञानिक डॉ एमके वर्णवाल ने कहा कि यह नया कीट फॉल आर्मी वर्म, जो बहुभुजी एवं तम्बाकू की इल्ली के परिवार का है। चालु रबी मौसम में इस कीट का प्रकोप पूरे भारत में जहाँ रबी मौसम में मक्के की खेती होती है, वहां पर भी देखी गई है। इस कीट का जीवन चक्र एवं इसकी नमी एवं तापमान की आवश्यकताओं को देखते हुए खरीफ मौसम में इसका गंभीर प्रकोप संभावित है। मक्का राज्य का एक प्रमुख खरीफ फसल है एवं इसका क्षेत्रफल और बढ़ने की संभावना है। अतः इस कीट का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। कीट की गंभीर अवस्था में सामान्य रूप से प्रचलित कीटनाशक इस-के ऊपर ज्यादा प्रभावी नहीं है। अतः समन्वित प्रयासों के तहत इसका निदान किया जाना जरूरी है। इसमें विभिन्न बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है।बोनी के पूर्व बीज को इमीडाक्लोप्रिड पावडर 2 ग्राम/किलो की दर से उपचारित कर ही बुआई करें। मानसून पूर्व शुष्क बोनी ज्यादा प्रभावी है। शुष्क बोनी नहीं करने पर मानसून वर्षा के साथ ही बुआई करें, विलंब न करें। देर से बोई गई फसल में इस कीट का प्रकोप ज्यादा गंभीर होता है।

डॉ वर्णवाल ने कहा कि अनुशंसित पौध अंतरण पर बुआई करें। संतुलित उर्वरकों का अनुशंसित मात्रा में, विशेषकर नत्रजन की मात्रा का प्रयोग अधिक न करें।जिन क्षेत्रों में खरीफ की मक्का ली जाती है उन क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन मक्का ना लें तथा अनुशंसित फसल चक्र अपनाएं। अंतवर्ती फसल के रूप में दलहनी फसल मूंग, उड़द लगाएं। प्रारंभिक अवस्था में लकड़ी का बुरादा, राख एवं बारीक रेत पौधे की पोंगली में डालें। जैविक कीटनाशक के रूप में बी.टी। 1कि.ग्रा। प्रति हेक्टेयर अथवा बिवेरिया बेसियाना 1.15 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव सुबह अथवा शाम के समय करें। लगभग 5 प्रतिशत प्रकोप होने पर रासायनिक कीटनाशक के रूप में फ्लूबेन्डामाइट 20, डब्ल्यू.डी.जी। 250ग्राम प्रति हेक्टेयर या स्पाइनोसेड 45 ईसी, 200-250 ग्राम प्रति हेक्टेयर या इथीफेनप्रॉक्स 10 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या एमिमामेक्टिन बेंजोएट 5 एस.जी। का 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर में कीट प्रकोप की स्थिति अनुसार 15-20 दिन के अंतरालन पर 2-3 बार छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव बुआई के बाद 15 दिन की अवधि में अवश्य करें।दानेदार कीटनाशकों का उपयोग पौधे की पोंगली में (5 से 7 दाने प्रति पोंगली) करें।

एमिटी युनिवर्सिटी, में निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा नुक्कड़-नाटक

संवाददाता रांची : सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 के दौरान सीएमपीडीआई के सतर्कता विभाग तथा एमिटी यूनिवर्सिटी, रांची के संयुक्त तत्वावधान में एमिटी युनिवर्सिटी, रांची में निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा नुक्कड़-नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर डा0 अजित कुमार पांडेय, निदेशक, एमिटी युनिवर्सिटी तथा पुश्कर, महाप्रबंधक (सतर्कता), सीएमपीडीआई ने छात्रों को सम्बोधित किया। इस अवसर पर अजित कुमार पांडेय ने भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर प्रकाश डाला तथा भ्रष्टाचार निवारण में छात्रों एवं युवकों की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने चरित्र निर्माण एवं जीवन में ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा की महत्ता को व्याख्यायित किया। मौके पर पुष्कर ने अपने अभिभाषण में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाये जाने की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य को रेखांकित किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं से

आह्वान किया कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में सक्रिय योगदान दें तथा सत्यनिष्ठा को अपनी जीवन शैली बनाएं।

''भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में युवाओं के समक्ष अवरोधक तथा उन्हें दूर करने के उपाय'' विषय पर आयोजित निबंध लेखन में कुल 24 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। एमिटी युनिवर्सिटी के ही छात्र-छात्राओं द्वारा बहुत ही सुन्दर लिखे एवं निर्देशित नुक्कड़-नाटक का मंचन भी किया गया। यह नाटक ''भ्रष्टाचार की व्यापकता तथा लोगों पर इसका दुष्प्रभाव'' से संबंधित था। यह नाटक बहुत ही मनोरंजक होने के साथ-साथ विचारोत्तेजक था। निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागी प्रथम-शिल्पी करक, द्वितीय-शशांक गुप्ता एवं तृतीय स्थान पर प्रतीक्षा सिंह रहीं। निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागी एवं नुक्कड़-नाटक की टीम को प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में एमिटी युनिवर्सिटी के डॉ0 शोभना चौधरी एवं सुश्री सायली राय की भूमिका अहम रही

व्यावसायिक प्रशिक्षकों को 15 दिन में करें बकाया वेतन का भुगतान

रांची: राज्य सरकार के विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में कौशल विकास योजना के तहत कार्यरत प्रशिक्षकों को सितंबर 2018 से अब तक बकाया मानदेय का भुगतान हर हाल में 15 दिन के भीतर कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान इससे जुड़ी शिकायत सामने आयी थी। इसपर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नोडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के संचालन के लिए जिन संस्थाओं से करार किया गया है, उनकी लापरवाही की वजह से मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने कहा कि जब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस मद में राशि नियमित रूप से जारी की जा रही है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कूलों में कार्यरत प्रशिक्षकों को हर महीने नियमित रूप से मानदेय का भुगतान हो।

हर प्रखंड में एक लीडर स्कूल विकसित करे: मुख्य सचिव

रांची संवाददाता: मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने शिक्षा विभाग को राज्य के हर प्रखंड में एक लीडर स्कूल विकसित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रयास यह हो कि यह स्कूल बुनियादी सुविधाओं से युक्त उन्नत किताबी शिक्षा, अनुशासन के साथ हर स्तर पर खेल, संगीत, वाद-विवाद जैसी अन्य गतिविधियों का मानक बन सके, ताकि दूसरे स्कूलों के छात्र-शिक्षक और अभिभावक भी वहां जाकर व्यवस्था को देखें, जानें और

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट ''साथ'' की समीक्षा बैठक

प्रेरणा ले सकें। उन्होंने औपचारिक किताबी शिक्षा के साथ मानसिक क्रियाशीलता पर फोकस करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि वक्त की जरूरत बच्चों का मानसिक स्तर व सामाजिक निपुणता बढ़ाकर उन्हें बेहतर नागरिक भी बनाना है। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट ''साथ'' की समीक्षा बैठक कर रहे थे।''साथ-ई''की यह है योजना ''साथ-ई'' के माध्यम से सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों की उनके क्लास के मानक के अनुरूप अपग्रेड करना है। अभी तक के सर्वे में पाया गया है कि बच्चे कक्षा पांच में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान का स्तर कक्षा तीन या दो का है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इन्हीं छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक तकनीक से अपग्रेड करने का प्रयास ''साथ-ई'' के माध्यम से चल रहा है। उसका सुखद परिणाम भी निकल रहा है।

भुखमरी से लड़ना है तो पर्यावरण सुधारें

अनिल पी. जोशी

वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) में दुनिया के 117 देशों में भारत 102वें स्थान पर है। आयरिश एजेंसी 'कंसर्न वर्ल्डवाइड' और जर्मन संगठन 'वेल्थहंगरहिल्फे' द्वारा संयुक्त रूप से तैयार इस इंडेक्स में भुखमरी और कुपोषण के मामले में भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। 2018 में भारत 119 देशों में 103 वें स्थान पर था जबकि साल 2000 में वह 113 देशों में 83 वें स्थान पर था। इस सूचकांक को तैयार करने के लिए विभिन्न देशों को चार प्रमुख संकेतकों के आधार पर रैंकिग दी जाती है- अल्प पोषण, बाल मृत्यु, पांच साल तक के कमजोर बच्चे और बच्चों का अवरुद्ध शारीरिक विकास।

आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम इस मामले में नीचे होते चले जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार आगे बढ़ने की बात की जाती है, दूसरी तरफ देश की एक बड़ी आबादी भुखमरी और कुपोषण से ग्रस्त है। दरअसल विकास को बड़ी इमारतों और गाड़ियों से नहीं मापा जा सकता। अगर देश में हर नागरिक का पेट नहीं भरा है, उसे संतुलित भोजन नहीं मिल रहा, वह स्वस्थ और प्रसन्न नहीं है तो यह डिवेलपमेंट अधूरा ही कहा जाएगा। भारत में विकास का जो विरोधाभास दिखाई देता है, उसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य ही नहीं, खेती-बाड़ी, बाल विकास, महिला कल्याण की सहायता से जुड़ी सारी मदों पर होने वाले खर्च के आंकड़े साफ बताते हैं कि सरकार की

प्राथमिकता सूची में इनकी जगह बहुत नीचे है। किसी भी कीमत पर विकास दर बढ़ाने में जुटी सरकार ने अपनी सारी आर्थिक ताकत देश का औद्योगिक माहौल सुधारने में झोंक रखी है। यह कोई गलत बात नहीं है लेकिन गहरी विषमताओं वाले भारतीय समाज में पहले से ही कमजोर सामाजिक निवेश का और कमजोर होना एक बड़ी आबादी के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सामाजिक निवेश बढ़ाने के साथ-साथ अब पर्यावरणीय चुनौतियों की ओर भी ध्यान देना होगा। हमें तमाम नीतियां इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर ही बनानी होंगी क्योंकि पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा को यह तत्व बड़े स्तर पर प्रभावित करने लगा है। जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक खाद्य उत्पादन और पोषण पर नकारात्मक असर डालना शुरू कर दिया है जिसकी मार सबसे ज्यादा कमजोर तबके पर पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग और वायुमंडल में बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ा जाना है, जो एक साथ मिलकर हीट वेव, सूखे और बाढ़ जैसी भीषण मौसमी घटनाओं को जन्म देती हैं। इन खतरों के चलते खाद्य उत्पादन कम होने और उनकी गुणवत्ता में कमी आने की भी आशंका है।

5 साल से कम उम्र के एक-तिहाई बच्चे कुपोषण या मोटापे से पीड़ित

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार 1990 के दशक के बाद से मौसम-संबंधी भीषण आपदाओं की संख्या दोगुनी हो गई है, जिससे प्रमुख फसलों की उत्पादकता प्रभावित हुई है। सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी जलवायु से संबंधित आपदाएं अंतरराष्ट्रीय आपदाओं का 80 फीसदी हैं। 2011-2016 के दौरान गंभीर सूखे ने विश्व के बड़े हिस्से को प्रभावित किया। अनुमान है कि इससे 51 देशों के लगभग 12.40 करोड़ लोग भयानक खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हुए थे। 2015-2016 के अल नीनो प्रभाव ने कई मुल्कों को अपनी चपेट में लिया, जहां गंभीर सूखा पड़ा। अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास आदि देशों में इसने 50 से 90 प्रतिशत तक फसलों को प्रभावित किया। आने वाले समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन से वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादकता तेजी से कम होगी। जाहिर है, इसका खामियाजा हाशिये पर पड़े और पहले से ही भुखमरी के सूचकांक में निचले स्तर पर मौजूद देशों को भुगतना पड़ेगा।

जलवायु परिवर्तन ने भोजन के पोषण स्तर को भी प्रभावित किया है। वातावरण में उच्च कार्बन डाइऑक्सा-इड सांद्रता फसलों में प्रोटीन, जिंक और लोहे की कमी पैदा करती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2050 तक अनुमानित 17.50 करोड़ नए लोगों को जिंक की कमी हो सकती है और अतिरिक्त 12.20 करोड़ लोग प्रोटीन की कमी की मार झेल सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें होगा जो अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग पूरी तरह से फसलों पर निर्भर हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में गरीब तबके का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खतरे में है। गौर करने की बात है कि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली काफी कमजोर है। खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव उनके स्वास्थ्य को बदतर बना देगा। ऐसे में भारत सरकार की प्राथमिकता जीडीपी नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मुट्ठी भर अमीर लोगों के विकास का सूचक है और सही मायने में यह उनके लिए भी बेहतर नहीं है। सचाई यह है कुपोषण तो संपन्न लोगों में भी एक समस्या का रूप ले चुका है। बदलती फूड हैबिट के कारण उनमें भी कुपोषण बढ़ा है। इसलिए विकास के सूचक जीवन से जुड़े होने चाहिए, न कि सुविधाओं और विलासिता से।

नदी और तालाब

ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती को देखते हुए भारत को घरेलू जरूरतों के लिए कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी। भारत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 68 फीसदी हिस्सेदारी ऊर्जा उत्पादन सेक्टर की है। पिछले कुछ समय से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की कोशिश जारी है। इसे और रफ्तार देने की जरूरत है। हमें पर्यावरण के अनुकूल कृषि नीति बनानी होगी। बिजली और यूरिया पर सब्सिडी तथा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को ऐसे राज्यों में भी धान और गन्ना जैसी फसलें लगाने के लिए प्रेरित करता है जहां पानी की उपलब्धता कम है। दूरदर्शी कृषि नीति न होने की वजह से पानी की कमी और पराली जलाने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप कृषि नीति बनाने और सूख रहे नदी-तालाबों को नया जीवन देने की जरूरत है।

E ZONE CARE

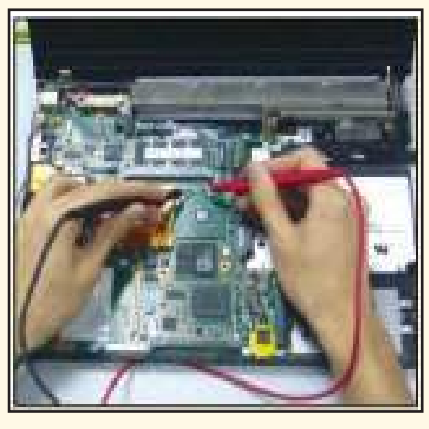

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

फोटो न्यूज

इकोफ्रेंडली है छठ पूजा :कच्चे मिट्टी से बनी हाथी कोशी। हाथी की यह प्रतिमा छठ पूजा में उपयोग होती है और गावों में यह आज भी कच्चे मिट्टी से ही बनती है ताकि यह विसर्जन में पूरी तरह से जल में घुल जाये।

लाह की चूड़ियां बनीं मतदाता जागरूकता का माध्यम

लाह की चूड़ी व लहटी के माध्यम से मतदाता जागरूकता के साथ-साथ एसएचजी की महिलाओं के आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय

संवाददाता

■ महिला मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनायी जा रही है मतदाता संदेश लिखी हुई लाह की चूड़ी व लहटी

रांची : विधानसभा चुनावों की घोषणा होते हीं मतदाता जागरूकता के लिये भी प्रयास शुरू हो गये हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इतने प्रयासों के बाद भी राज्य में वोट प्रतिशत में कोई खास वृद्धी नहीं हुयी है। देवघर में मतदान के प्रति जागरूकता बढाने के लिये लाह की चूड़ियां पर वोट देने का संदेश अंकित करवाया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव, 2019 में महिला मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वृहत स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसके तहत महिलाओं की अभिरुचि वाले विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्हें मतदाता जागरूकता सन्देश दिए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं अपने मताधिकार के महत्व को समझें और महिला मतदाताओं के मतदान प्रतिशत में वृद्धि लायी जा सके।इसी कड़ी में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत देवघर जिला के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लाह की चूड़ी-लहटी में आकर्षक ढंग से विभिन्न मतदाता जागरूकता सन्देश लिख कर लोगों से वोट करने की अपील की गयी है। सिर्फ इतना हीं नहीं इन महिलाओं द्वारा स्व-हस्तनिर्मित लाह की चूड़ियों को स्वयं तो पहन कर लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित तो किया जा रहा है, साथ हीं उसका विक्रय कर अच्छी-खासी आमदनी भी की जा रही है। इससे एक तरफ जहाँ इनके आय की स्रोत में वृद्धि हुई है, वहीं इसके माध्यम से महिला मतदाताओं के बीच जागरूकता सन्देश भी प्रेषित हो रहे हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि जल्द हीं इन लाह की लहटी व चूड़ियों को विक्रय हेतु बाजारों में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इसके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के साथ-साथ जेएसएलपीएस की महिलाओं के आय के स्रोत में वृद्धि लायी जा सके। साथ हीं उनके द्वारा सभी जिलावासियों से अपील की गयी है कि आगामी 16 दिसंबर को मधुपुर एवं देवघर विधानसभा क्षेत्र और 20 दिसंबर को सारठ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान के दिन वे मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदान करना सिर्फ हमारा अधिकार हीं नहीं बल्कि दायित्व भी है और हम सभी को चाहिए कि हम एक जागरूक मतदाता बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

उम्र अठारह पूरी है, मत देना बहुत जरूरी है

सोहराई परब के मौके पर किया गया बरद भीड़का

सिदाम महतो

रांची/बुण्डू: सोहराई पर्व के मौके पर बुण्डू के एडकेया ग्राम में बरद(बैल) भीड़का(खेला) का आयोजन रसिक संघ के द्वारा किया किया गया।गांव के सात बैलों को बारी-बारी से अखाड़ा के खुंटा पर बाँधा गया। रसिकों ने ढोल नगाड़े और सोहराई गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महतो महिंदर उपस्थित रहे। रसिक संघ के परमेश्वर महतो,जयपाल महतो, नागेश्वर महतो,अभिराम महतो,नकुल महतो,भीष्मदेव महतो,रोहित महतो,त्रिलोक महतो,बासुदेव महतो,धीरेन्द्र महतो,सम्भद महतो,घासीया महतो,सन्तोष महतो,काली महतो, लक्ष्मण महतो, सबरण महतो,कांशी महतो,घूरन महतो मौजूद रहे इसके अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में बलराम,हेमन्त, पवन , राजेश, पंकज, सुधीर, मुन्ना, नरेंद्र, सुनील, संजय, विकास, धनपति , शशिभूषण , धीरज,सुखदेव,सुभाष, रमेश का अहम योगदान रहा।

15 लाख भारतीयों की मौत हो सकती है

जलवायु परिवर्तन के कारण साल 2100 में भारत में तापमान इस कदर बढ़ जाएगा कि हर साल लगभग 15 लाख लोगों की मौत हो सकती है। मरने वालों की इस संख्या की यदि तुलना करें तो यह संख्या वर्तमान में भारत में सभी संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों की तुलना में अधिक बैठती है। भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण 2100 तक भारत के औसत सालाना तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी संभव है। यानी सालभर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाले बेहद गर्म दिनों की औसत संख्या 5.1 (2010) से आठ गुना बढ़कर 42.8 डिग्री तक पहुंच जाएगी।

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब द्वारा टाटा सेंटर फार डेवलपमेन्ट के सहयोग से किए गए अध्ययन में पाया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन एवं मौसम में बदलावों के मानव व अर्थव्यवस्था पर हुए प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया गया। गर्म दिनों की बढ़ती संख्या के साथ अनुमान है कि 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में से 16 राज्य पंजाब से अधिक गर्म होंगे, जो वर्तमान में भारत का सबसे गर्म राज्य है, जिसका औसत सालाना तापमान ठीक 32 डिग्रीसेंटीग्रेड से नीचे है (2010)। पंजाब 2100 में भारत का सबसे गर्म राज्य बना रहेगा।

PICK - UP COMPUTERS
A Complete Solution of Computer & Home Appliances
Our Service :- Assembled Computer, Branded Desktop & Laptop Peripherals Networking, Hardware & Software, Accessories, Projector
Exchange Old Pc to Laptop/Desktop
लीपि व अन्य कंपनियों के कांपटिबल काट्रिज के के लिये संपर्क करें
C.C.T.V कैमरा के लिए सम्पर्क करें।
सबसे सस्ता सबसे बढ़िया
Logitech SONY acer ASUS intex LG FRONTECH
H.O.:- HAWAI JAHAJ KOTHI, OPP. YAMAHA SHOWROOM, KANKE ROAD, RANCHI
Mob. - 9308466589, 9334729492

जल कौशल के जानकार थे भारतीय

दक्षिण भारत के विजयनगर (इसकी राजधानी कर्नाटक के हम्पी के नजदीक थी) के प्रसिद्ध राजाओं (1336-1564) ने सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने पर काफी जोर दिया। वे इसे खेती में सुधार के लिए जरूरी मानते थे। विजयनगर के शासकों में सबसे प्रसिद्ध और निपुण राजा कृष्णदेव राय (1509-1530) ने एक बार कहा था कि किसी भी राज्य की उन्नति उसके अधीन आने वाले क्षेत्र पर निर्भर करती है। अगर जमीन कम है तो समृद्धि लाने का तरीका है कि जलाशयों और सिंचाई के लिए नालों का निर्माण कराया जाए और गरीब किसानों को करों आदि से मुक्त किया जाए। विजयनगर के राजाओं ने न सिर्फ सिंचाई के लिए उपयुक्त जलाशयों का निर्माण करवाया, बल्कि कुछ हद तक, लोगों को स्वयं भी सिंचाई साधन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सिंचाई के तीन प्रमुख प्रकार के स्रोत हैं, जलाशय, नदियों पर निर्मित बांध और उनसे निकाले गए नाले और कुएं। विजयनगर राज्य ने इन तीनों पर ध्यान दिया। सन 1369 में विजयनगर के पहले शासक वंश के युवराज भास्कर बावादुर ने आंध्र प्रदेश के आधुनिक कुडप्पा जिले में एक बड़े जलाशय का निर्माण कराया, जो अकाल से प्रभावित था। इसे बनवाने में एक हजार मजदूरों और 100 बैलगाड़ियों की जरूरत पड़ी थी, जिन्हें इस जलाशय की दीवारों के निर्माण के लिए पत्थर जमा करने के लिए लगाया गया था। इसे बनवाने में पूरे दो वर्ष लगे थे। यह जलाशय आज भी प्रयोग में लाया जाता है। राजा बुक्का राय द्वितीय (1405-1406) के आदेशानुसार एक जलसूत्र (जल इंजीनियर), सिंगया भट्टा ने हेन्न नदी के पानी को जल मार्गों की सहायता से पेनूगोनला स्थित सिरुवेरा जलाशय तक पहुंचाया था।

सेंधा नमक : भारत से कैसे गायब कर दिया गया!

प्रमोद मिश्र

आप सोच रहे होंगे की ये सेंधा नमक बनता कैसे है ?? आइये आज हम आपको बताते हैं कि नमक मुख्य कितने प्रकार होते हैं। एक होता है समुद्री नमक दूसरा होता है सेंधा नमक। सेंधा नमक बनता नहीं है पहले से ही बना बनाया है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को 'सेंधा नमक' या 'सैन्धव नमक', लाहोरी नमक आदि आदि नाम से जाना जाता है ।जिस्का मतलब है 'सिंध या सिन्धु के इलाक़े से आया हुआ'। वहां नमक के बड़े बड़े पहाड़ है सुरंगे है ।वहां से ये नमक आता है। मोटे मोटे टुकड़ो मे होता है आजकल पीसा हुआ भी आने लगा है यह ह्रदय के लिये उत्तम, दीपन और पाचन मे मदद रूप, त्रिदोष शामक, शीतवीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला, पचने मे हल्का है। इससे पाचक रस बढ़्ते हैं। तों अंत आप ये समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकले। काला नमक ,सेंधा नमक प्रयोग करे, क्यूंकि ये प्रकृति का बनाया है ईश्वर का बनाया हुआ है। और सदैव याद रखे इंसान जरूर शैतान हो सकता है लेकिन भगवान कभी शैतान नहीं होता। भारत मे 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था विदेशी कंपनिया भारत मे नमक के व्यापार मे आज़ादी के पहले से उतरी हुई है , उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भली जनता को आयोडिन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है, हुआ ये कि जब ग्लोबलाईजेशन के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियो (अनपूर्णा,कैपटन कुक) ने नमक बेचना शुरू किया तब ये सारा खेल शुरू हुआ ! अब समझिए खेल क्या था ?? खेल ये था कि विदेशी कंपनियो को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है तो पूरे भारत मे एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नामक खाओ , आयोडीन युक्त नमक खाओ ! आप सबको आओडीन की कमी हो गई है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है आदि आदि बातें पूरे देश मे प्रायोजित ढंग से फैलाई गई । और जो नमक किसी जमाने मे 2 से 3 रूपये किलो मे बिकता था । उसकी जगह आओडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रूपये प्रति किलो और आज तो 20 रूपये को भी पार कर गया है। दुनिया के 56 देशों ने अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले Ban कर दिया अमेरिका मे नहीं है जर्मनी मे नहीं है फ्रांस मे नहीं ,डेन्मार्क मे नहीं , डेन्मार्क की सरकार ने 1956 मे आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया क्यों ?? उनकी सरकार ने कहा हमने मे आयोडीन युक्त नमक खिलाया! (1940 से 1956 तक) अधिकांश लोग नपुंसक हो गए! जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा हो गया ! उनके वैज्ञानिको ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ तो उन्होने बैन लगाया। और शुरू के दिनो मे जब हमारे देश मे ये

आयोडीन का खेल शुरू हुआ इस देश के बेशर्म नेताओ ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत मे बिक नहीं सकता ।वो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट मे मुकदमा दाखिल किया और ये बैन हटाया गया। आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था सब सेंधा नमक ही खाते थे ।

सेंधा नमक के फ़ायदे :- सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियों पर नियन्त्रण रहता है ।क्योंकि ये अम्लीय नहीं ये क्षारीय है । क्षारीय चीज जब अमल मे मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है और रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं । ये नमक शरीर मे पूरी तरह से घुलनशील है। और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास, व्रत मे सब सेंधा नमक ही खाते है। तो आप सोचिए जो समुंदरी नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है ??

सेंधा नमक शरीर मे 97 पोषक तत्वो की कमी को पूरा करता है ! इन पोषक तत्वो की कमी ना पूरी होने के कारण ही लकवे का अटैक आने का सबसे बढ़ा जोखिम होता है सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि यह आपको इसलिये खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। यह पाचन में सहायक होता है और साथ ही इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। यही नहीं आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण भाष्कर, पाचन चूर्ण आदि में भी प्रयोग किया जाता है।

समुद्री नमक के भयंकर नुकसान
ये जो समुद्री नमक है आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप मे ही बहुत खतरनाक है ! क्योंकि कंपनियां इसमे अतिरिक्त आयोडीन डाल रही है। अब आयोडीन भी दो तरह का होता है एक तो भगवान का बनाया हुआ जो पहले से नमक मे होता है । दूसरा होता है industrial iodine ये बहुत ही खतरनाक है। तो समुद्री नमक जो पहले से ही खतरनाक है उसमे कंपनिया अतिरिक्त industrial iodine डाल कर पूरे देश को बेच रही है। जिससे बहुत सी गंभीर बीमरियां हम लोगो को आ रही है । ये नमक मानव द्वारा क़ारखानों में निर्मित है। आम तौर से उपयोग मे लाये जाने वाले समुद्री नमक से उच्च रक्तचाप डाइबिटीज़, आदि गंभीर बीमारियो का भी कारण बनता है । इसका एक कारण ये है कि ये नमक अम्लीय होता है । जिससे रक्त अम्लता बढ़ती है और रक्त अम्लता बढ़ने से ये सब 48 रोग आते है ।ये नमक पानी कभी पूरी तरह नहीं घुलता हीरे की तरह चमकता रहता है इसी प्रकार शरीर के अंदर जाकर भी नहीं घुलता और अंत इसी प्रकार किडनी से भी नहीं निकल पाता और पथरी का भी कारण बनता है । ये नमक नपुंसकता और लकवा का बहुत बड़ा कारण है समुद्री नमक से सिर्फ शरीर को 4 पोषक तत्व मिलते है ! और बीमारियां जरूर साथ मे मिल जाती है ! रिफाइंड नमक में 98% सोडियम क्लोराइड ही है शरीर इसे विजातीय पदार्थ के रुप में रखता है। यह शरीर में घुलता नही है। इस नमक में आयोडीन को बनाये रखने के लिए Tricalcium Phosphate, Magnesium Carbonate, Sodium Alumino Silicate जैसे रसायन मिलाये जाते हैं जो सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल होते है। विज्ञान के अनुसार यह रसायन शरीर में रक्त वाहिनियों को कड़ा बनाते हैं, जिससे ब्लाक्स बनने की संभावना और आक्सीजन जाने मे परेशानी होती है। जोड़ो का दर्द और गढिया, प्रोस्टेट आदि होती है। आयोडीन नमक से पानी की जरुरत ज्यादा होती है। 1 ग्राम नमक अपने से 23 गुना अधिक पानी खींचता है। यह पानी कोशिकाओ के पानी को कम करता है। इसी कारण हमें प्यास ज्यादा लगती है। पांच हजार साल पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में भी भोजन में सेंधा नमक के ही इस्तेमाल की सलाह दी गई है। भोजन में नमक व मसाले का प्रयोग भारत, नेपाल, चीन, बंगलादेश और पाकिस्तान में अधिक होता है। आजकल बाजार में ज्यादातर समुद्री जल से तैयार नमक ही मिलता है। जबकि 1960 के दशक में देश में लाहौरी नमक मिलता था। यहां तक कि राशन की दुकानों पर भी इसी नमक का वितरण किया जाता था। स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता था। समुद्री नमक के बजाय सेंधा नमक का प्रयोग होना चाहिए। आप इस अतिरिक्त आयोडीन युक्त समुद्री नमक खाना छोड़िए और उसकी जगह सेंधा नमक खाइये !!

सिर्फ आयोडीन के चक्कर में समुद्री नमक खाना समझदारी नहीं है, क्योंकि जैसा हमने ऊपर बताया आयोडीन हर नमक मे होता है सेंधा नमक मे भी आयोडीन होता है बस फर्क इतना है इस सेंधा नमक मे प्राकृतिक के द्वारा भगवान द्वारा बनाया आयोडीन होता है इसके इलावा आओडीन हमें आलू, अरवी के साथ-साथ हरी सब्जियों से भी मिल जाता है। (*लेखक के अपने विचार हैं*)

दुग्ध खरीद कीमत स्थिर रहने के आसार

दिलीप कुमार झा

ठंड का मौसम शुरू होते ही पूरे देश में दुग्ध आपूर्ति बढ़ जाती है। ऐसे में डेरी कंपनियां दुग्ध खरीद और स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एसएमपी) की कीमतें मौजूदा स्तर के आसपास स्थिर रहने की उम्मीद कर रही हैं। डेरियों के लिए दुग्ध खरीद कीमतें महाराष्ट्र में बाढ़ से पहले के 28 रुपये प्रति लीटर से 10 प्रतिशत तक बढ़कर 31 रुपये पर पहुंच गई हैं। अगस्त के पहले पखवाड़े में पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ से गंभीर संकट पैदा हो गया और इसमें हजारों दुधारू मवेशी बह गए। इसी तरह अन्य दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों में बाढ़ से उत्पादन प्रभावित हुआ है जिससे देश में कुल दुग्ध उत्पादन घटा है।

हालांकि मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान दुग्ध मांग तेजी से बढ़ी है जिससे डेरी कंपनियों ने किसानों के फायदे के लिए दुग्ध खरीद कीमतें बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। डायनेमिक्स ब्रांड के डेरी उत्पादों की उत्पादक श्रीबर डायनेमिक्स डेरीज के प्रबंध निदेशक अमिताभ रे ने कहा, 'मौजूदा समय में दुग्ध खरीद कीमत 31 रुपये प्रति लीटर पर है जिससे आपूर्ति की तुलना में ज्यादा मांग की वजह से पिछले तीन महीनों में कीमतों में अच्छी तेजी का पता चलता है। हालांकि अभी यह अनुमान लगाना जल्दबाजी है कि आगामी सीजन कैसा रहेगा, क्योंकि दुग्ध खरीद कीमत मौजूदा स्तर से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती हैं।'दिलचस्प तथ्य यह है कि डेरी कंपनियों ने दूध की कीमतें मई में 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाई थीं, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं थी। इसके अलावा एसएमपी की कीमतें पिछले तीन महीनों में 15 प्रतिशत से बढ़कर 170-300 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच पहुंच गई हैं। अमूल ब्रांड के डेरी उत्पाद बेचने वाली गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक आर एस सोढ़ी ने कहा, 'औसत मॉनसून बारिश इस साल पूरे भारत में दर्ज की गई। इसके अलावा, किसानों को अब अच्छी कीमत भी मिल रही है जिससे चारे की बढ़ती लागत पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। चारे की कीमतें पिछले एक साल में 40 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। अब किसान नए पशु खरीदने और ज्यादा दुग्ध तैयार करने के लिए

प्रोत्साहित होंगे जिससे निश्चित रूप से तरलीकृत दूध की आपूर्ति इस सीजन में बढ़ेगी। इस वजह से हमें एसएमपी की कीमतें मौजूदा 270-300 रुपये प्रति किलो की रेंज से ज्यादा बढने् का अनुमान नहीं है।'

गर्मी का मौसम समाप्त होने के साथ ही दुग्ध उत्पादन बढने् लगा है। नवंबर से लेकर मार्च तक की पांच महीने की अवधि को दूध की ज्यादा आपूर्ति वाला समय समझा जाता है। इसी तरह, अप्रैल से लेकर अक्टूबर के अंत तक की सात महीने की अवधि को कम दुग्ध आपूर्ति वाला सीजन माना जाता है। इस सीजन के दौरान डेरी कंपनियां सामान्य तौर पर अतिरिक्त दूध को एसएमपी में परिवर्तित करती हैं जिससे कि कमजोर आपूर्ति वाली अवधि में उपभोक्ताओं को तरलीकृत और पाउडर वाले दूध, दोनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

दुग्ध कीमत रुझान में बदलाव से महाराष्ट्र सरकार ने दुग्ध कीमतों में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए अगस्त 2018 से जनवरी 2019 के बीच मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए दुग्ध प्रोसेसिंग के लिए 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी की घोषणा की थी। तब दूध की कीमतें 19-20 रुपये प्रति लीटर पर थीं। हालांकि पिछले एक साल के दौरान तरलीकृत दूध और एसएमपी की कीमतें 25 प्रतिशत और 26 प्रतिशत बढ़ी हैं। इलारा सिक्योरिटीज (इंडिया) में विश्लेषक सागरिका मुखर्जी का कहना है, 'पिछली तिमाही में सभी डेरी कंपनियों ने घी और तरलीकृत दूध की कीमतें 3-6 प्रतिशत और 5 प्रतिशत बढ़ाई थीं। पनीर की कीमतें भी पिछले एक साल में 8-21 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। कुल मिलाकर डेयरी उद्योग सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगा, लेकिन एबिटा में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की कमी आएगी क्योंकि दूध कीमतों में वृद्धि पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया।

ओजोन परत के नुकसान की चेतावनी देगी मशीन

दुनिया भर में ओजोन प्रदूषण एक बड़ा खतरा है जो की हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है। पर इससे बचने के लिए ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली विकसित करने में सफलता हासिल की है, जो क्षेत्रीय स्तर पर 24 घंटे पहले ही इसका पूर्वानुमान कर सकती है। इससे ओजोन के बढ़ते स्तर से बचने में मदद मिलेगी, साथ ही स्वास्थ्य संबधी जोखिम कम हो जायेगा।

पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और इस पेपर के संबंधित लेखक यूनसो चोई ने बताया कि उन्होंने न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करके एक ऐसा मॉडल बनाया है जो अर्टिफिकल इंटेलिजेंस पर चलता है ।जो वर्तमान परिस्थितियों का जायजा लेकर अगले 24 घंटों के लिए वातावरण में ओजोन के स्तर की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः मनोज * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN00962, email:greenrevolt2019@gmail.com. Ph. 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।